बुनियादी ढांचा आधारभूत ढांचों का विकास किसी भी देश की क्षमता का स्पष्ट प्रमाण होता है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत ने आधारभूत ढांचों के विकास में गर्व करने योग्य प्रगति दर्ज की है। रेलवे, एयरपोर्ट, सड़कमार्ग, दूरसंचार, बंदरगाह जैसे क्षेत्रों के विकास की कहानी भारत की कुशल नीतियों को बयां करती है। भारत बुनियादी ढांचों के विकास में अब वैश्विक स्तर छू रहा है।

प्रगति के नए शिखर छू रहे बुनियादी ढांचे

डॉ. ब्रजेश कुमार तिवारी, असोसिएट प्रोफेसर, अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जेएनयू

आजादी के 77 वर्षों के बाद, भारतीय आधारभूत ढांचों के संदर्भ में देश अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से 'मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर' की ओर बढ़ चुका है, फिर भी आज विश्व बैंक के बुनियादी ढांचा स्कोर में भारत का दुनिया में 47वां स्थान है। यहीं वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के मामले में दुनिया के 140 देशों में भारत का स्थान 70वां है। भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन का अनुमान है कि बुनियादी ढांचे पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपये से सकल घरेलू उत्पाद में 2.5 से 3.5 रुपये का लाभ होता है। वर्ष 1948 की औद्योगिक नीति संकल्प ने हमारे समक्ष एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रस्ताव रखा। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में परिवहन एवं संचार पर व्यय 1300 करोड़ रुपये था। यह हर योजना के कुल व्यय का 26 फीसदी था।

1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ। योजना में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के जलविद्युत बांधों– भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और नागार्जुन सागर का प्रावधान किया गया था। अकाल की पृष्ठभूमि को देखते हुए, भारत की सूखी भूमि की सिंचाई हेतु दामोदर वैली कॉरपोरेशन, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजना थी।

सड़क नेटवर्क में सुधार

भारतीय सड़क नेटवर्क की कुल लंबाई 1951 में 0.399 मिलियन किमी से बढ़कर आज 6.37 मिलियन किलोमीटर से अधिक हो गई है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में दो सड़क परियोजनाएं शुरू की गईं– स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज ने राजमार्गों के एक नेटवर्क के माध्यम से चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ा, जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की योजना पूरे भारत में असंबद्ध गांवों के लिए सभी मौसमों के अनुकूल सड़कों के एक नेटवर्क के रूप में बनाई गई। मोदी सरकार की भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किमी सड़कें बनेंगी।

एनआईपी योजना

2019 में शुरू की गई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) को पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान द्वारा पूरक किया गया है। इसका उद्देश्य भारतमाला, सागरमाला, उड़ान आदि जैसी कनेक्टिविटी ढांचा योजनाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत एक साथ लाना है। भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में 35 मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों का एक नेटवर्क विकसित करने की योजना है।

देश के गौरव

दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग –'अटल सुरंग'; दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल– चिनाब ब्रिज; लद्दाख ने एशिया की सबसे लंबी सुरंग– जोजिला सुरंग; ब्रह्मपुत्र पर बोगीबील ब्रिज, पूर्वोत्तर में जवाहरलाल ब्रिज और ढोला–सदिया ब्रिज।

कुछ चुनौतियां भी

इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का भंडारण बाजार 2022 के बाद से 16 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र में हालात कई सतहों से जूझ रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भले भारत की स्थिति पांचवीं हो, मगर विकास का हिस्सा बहुतों तक अभी नहीं पहुंच रहा है। ग्रामीण–शहरी असमानता को दूर करने के लिए सड़क, विद्युतीकरण, स्वास्थ्य सुविधा और डिजिटल कनेक्टिविटी सहित ग्रामीण अवसंरचना में निवेश को प्राथमिकता दी जाए। पूंजीगत व्यय बढ़ने के बावजूद विश्व बैंक के अनुसार भारत को अवसंरचनात्मक अंतराल लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर का होने का अनुमान है। 1.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के सपने को हकीकत में बदलने के लिए 2030 तक देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण में 4.51 ट्रिलियन डॉलर का निवेश करने की जरूरत है। इसलिए आधारभूत ढांचे पर खर्च जीडीपी का वर्तमान 4 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी तक करना होगा।

11.11
लाख करोड़ रु. आवंटित हुए ढांचागत विकास के लिए, इस बार के बजट में

आठ प्रमुख आधारभूत उद्योगों की वृद्धि

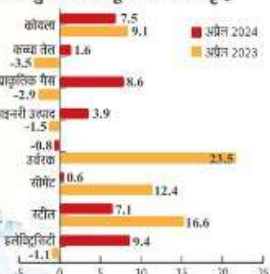

सड़क निर्माण प्रतिदिन (किमी.)

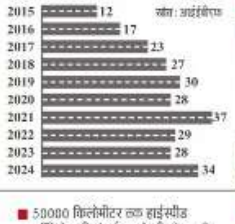

विकास की ओर तेजी से बढ़ते कदम

- 11 प्रतिशत राशि अधिक आवंटित की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट के लिए पिछले वर्ष की तुलना में। साथ ही राज्यों के विकास को बढ़ावा देने के लिए लंबी अवधि में ब्याज छूट के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- 50000 किलोमीटर लंबा हाईस्पीड कॉरिडोर की लंबाई बढ़ाने की योजना है वर्ष 2047 तक। वर्ष 2023 के आंकड़ों अनुसार यह 3913 किलोमीटर है।
- 149 से बढ़ाकर 220 तक एयरपोर्ट बनाने की योजना है अगले 5 से 7 सालों में।
- 30 से अधिक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है भारत में।
- तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है भारत विमानन क्षेत्र में।
- दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है भारत 2024 में।

हमारी बुनियादी क्षमता

बढ़े एयरपोर्ट
2014 74
2024 149

बढ़ा सड़क नेटवर्क
1951 0.399
2024 6.37
मिलियन किमी.

बढ़ा रेलवे नेटवर्क
1947 25,170
2024 1.45
लाख किलोमीटर

बिजली का उत्पादन

1947 1,362 मेगावाट
2023 1,968 टेरावाट

राजमार्गों का विस्तार
किलोमीटर में

राष्ट्रीय राजमार्ग 146145
राज्य राजमार्ग 179535

बढ़ता गया रेलवे नेटवर्क

सरकार की दिसंबर, 2023 तक रेलवे नेटवर्क के कुल विद्युतीकरण की कल्पना अपने अंतिम चरण में है। आज भारत का दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्ततम रेल नेटवर्क 7,000 से अधिक स्टेशनों पर संचालित होता है। भारत के पास वर्तमान में दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है, जल्दी ही यह तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा।

नागरिक उड्डयन का वैश्विक प्रसार

भारत का विमानन क्षेत्र दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 'विजन 2040' रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक भारत में 190-200 तक कामकाजी हवाई अड्डे होंगे।

बिजली व परमाणु ऊर्जा

भारत दुनिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिजली की औसत उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 20.5 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.5 घंटे तक पहुंच गई है। सरकार ने 2019 तक सभी 18,452 गांवों का विद्युतीकरण किया, जबकि 1950 में 3,061 गांवों का विद्युतीकरण किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पोखरण में अपना पहला भूमिगत परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा (पोखरण-1) 18 मई, 1974 को किया था। बाद में अटलजी के नेतृत्व में 11 और 13 मई, 1998 को पांच और भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए।

डिजिटल ढांचे का आगाज

ट्रांसयूनियन सीआईबीआईएल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक इंटरनेट के कुल नए यूजर में लगभग 56 फीसदी ग्रामीण भारत से होंगे। जनधन खाता, जो मोबाइल नंबरों को आधार कार्ड और बैंक खातों से जोड़ता है, यूपीआई व सरकारी योजना के लाभार्थियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का एक प्रमुख उपकरण बन गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार

देश में सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति लाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) शुरू हुआ। यह संस्था दूरसंचार विभाग का एक स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है और सरकार को डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, भारत नेट, मेक इन इंडिया जैसे प्रमुख कार्यक्रमों को साकार करने में मदद करता है।

बंदरगाहों का विस्तार

विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीआई) रिपोर्ट 2023 के अनुसार, भारतीय बंदरगाहों का 'टर्न अराउंड टाइम' 0.9 दिन तक पहुंच गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (1.5 दिन) से बेहतर है। देश की कुल बंदरगाह क्षमता मौजूदा 2,600 एमटीपीए (एमएन टन प्रति वर्ष) से बढ़कर 2047 में 10,000 एमटीपीए से अधिक हो जाएगी। 2022 तक, देश में 224 बंदरगाह थे।

अंतरिक्ष अनुसंधानों ने पकड़ी गति

भारत के अंतरिक्ष मिशनों ने ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिक ज्ञान में योगदान दिया है। चंद्रयान-1, मंगल कक्षित्र मिशन, एस्ट्रोसैट और चंद्रयान-2 जैसे मिशन इसी का उदाहरण हैं।